

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 290/2016 (अपील)

उपनाम

1. मांगीलाल आत्मज लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा (राज०)
2. रामप्यारी बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी गंवरलाल जाति माली निवासी पाटनपोल, कोटा
3. शान्ति बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी गोपाल जाति माली निवासी ग्राम सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा

(अपीलापटान)

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज जमना लाल
2. बद्रीलाल आत्मज सत्यनारायण जी
3. विजेन्द्र कुमार आत्मज सत्यनारायण जी
4. अनोख बाई बेवा सत्यनारायण जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम हिगोनियां तहसील कनवास जिला कोटा

(रेस्पोंडेण्टान)

- उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलापट)
2. श्री धीरेन्द्र मालव (अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० टी० एक्ट 1955

बनाराजगी आदेश दिनांक 25.08.2016

न्यायालय तहसीलदार कनवास

निर्णय दिनांक : 16.12.2019

1. अपीलापट द्वारा जय अभिभाषक यह अपील इस आशय की पेश की कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलापट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अपीलापट स्वीकार कर ली गयी जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवेधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय से इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को प्रथमतः सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । राज्य सरकार के परिपत्र के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंड के प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत में भेजा नहीं गया और न ही ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त की । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश राज्य सरकार के परिपत्र नोट्स 1982 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलापटान की आराजी पर से होकर रेस्पोंड का कभी भी रास्ता नहीं रहा है और गरी रेस्पोंड द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया कि अपीलापट की आराजी में कदीमी सार्वजनिक प्रचलित रास्ता रेस्पोंड का रहा हो । रेस्पोंड द्वारा ऐसा कोई तथ्य व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है

जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट की आराजी पर से रेस्पो० का रास्ता हो । अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी के चारों ओर पत्थर कोट कदिमी समय से कर रखा है इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट की आराजी पर रेस्पो० का कभी रास्ता नहीं रहा है । रेस्पो० का पूर्व से ही नहर पर से होकर प्रचलित रास्ता रहा है जिस पर से होकर रेस्पो० अपनी आराजी पर हमेशा की भांति आजा भी आता जाता रहा है । उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं० 303,303/1,312, 314, 315, 304 के सभी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ख० नं० 312, 313,314, 315 से लगवा आवां से सांगोद वाला रोड निकल रहा है उक्त रोड पर से कभी भी रेस्पोडेन्ट का रास्ता नहीं रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार के सबूत के रेस्पो० का रास्ता होना स्वीकार कर लिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट की आराजी पास में कोई सरकारी भूमि स्थित नहीं है । खसरा नं० 314 की आराजी रामदेव आ० कान्हा जाति चमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व खसरा नं० 315 मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति व नाबालिग मूर्ति मंदिर के हितों को प्रोजेक्ट किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० के पक्ष में आदेश प्रदान कर दिया । अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये हैं कि प्रार्थी को बिना नोटिस व जानकारी के आदेश प्रदान किया है जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 14.11.2016 को थाने में उपस्थित होने पर हुई जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 17.11.2016 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.08.16 से 14.11.16 की अवधि कन्डोन फरमाई जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई रेस्पो० नं० 1 लगायत 4 की ओर से श्री धीरेन्द्र मालव एड० ने वकालत नामा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि राज्य सरकार के परिपत्र के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० के प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत में भेजा नहीं गया और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त की इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश राज्य सरकार के परिपत्र नोटिस 1982 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बिना रेस्पोडेन्ट की सुनवाई करे नया रास्ता कायम किया गया । वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का रास्ता चालू है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।


4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने अपनी बहस में जाहिर किया कि रेस्पो० नं० 1 लगायत 4 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम जगदीशपुरा तहसील कनवास में ख० नं० 303/1 की 3.05 है० भूमि स्थित है उक्त आराजी पर जाने के लिए पुराना रास्ता सांगोद कनवास मुख्य सड़क से खसरा नं० 314 व 313 में मध्य स्थित सरकारी भूमि पर होता हुआ ख० नं० 304 की दक्षिणी मेड चलकर पश्चिमी मेड पर होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी पर आता है । उसी रास्ते का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपर सुनवाई की जाकर नियमानुसार रास्ता कायम किया गया है । जो वर्तमान में रास्ता चालू है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि० एक्ट में देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि० एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.09.82 के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को प्रथम 45 दिन तक सुनवाई व निर्णय करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा उक्त प्रकरण रेस्पोंडेन्ट को प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत में भेजा नहीं गया और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई राय ही प्राप्त नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण भेरूलाल, जगन्नाथ, रामकिशन, कालूलाल के बयान व पटवारी हत्का कनवास की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2016 के आधार पर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट को मौका निरीक्षण हेतु नोटिस नहीं दिया गया तथा उन्हें सुनवाई / साक्ष्य का भी पूर्ण अवसर दिया जाता नहीं पाया जाता है।

6. उपर्युक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत हिंगोनियां पंचायत समिति सांगोद को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह संबंधित समस्त पक्षकारान की सुनवाई कर बाद साक्ष्य विधि सम्मत निर्धारित अवधि में निर्णय पारित करें।

7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
मुद्रा


(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा